



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 508] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 1971/अश्विन 21, 1893

No. 508 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 1971/ASVINA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(GRIM MANTRALAYA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October 1971

S.O. 3857.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas I, V. V. Giri, President of India, had on 16th October, 1969, made an Order, suspending for a period of one year the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Manipur and making certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Manipur in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I had on 13th October, 1970 and 14th April, 1971 made further Orders continuing the suspension of operation of the provisions of the Act for a further period of six months on each occasion from the date on which the first-mentioned Order would otherwise have expired;

And whereas after considering the information received by me, I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of the Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by me under the

first-mentioned Order should continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct—

(a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of the first-mentioned Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the said Order shall continue to be operative, for a further period of three months with effect from the 16th day of October, 1971; and

(b) that for the words "two years" occurring in clause (a) of the first-mentioned Order as subsequently amended, the words "two years and three months" shall be substituted.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 10/26/71-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

NEW DELHI-4,
The 12th October, 1971.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1971

एस० ओ० 3857—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

आदेश

यतः मैंने, व० वे० गिरि, भारत के राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर, 1969 को संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) के कतिपय उपबन्धों का प्रवर्तन मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित करके हुए, और कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाते हुए जो मुझे पूर्वोक्त अवधि में मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक और समीचीन लगे थे, एक आदेश किया था।

और यतः मैंने, उस तारीख से, जिसको प्रथम-उल्लिखित आदेश का अन्यथा अवसान हो जाता, प्रत्येक अवसर पर छः मास की और अवधि के लिए अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन का निलम्बित जारी रखते हुए 13 अक्टूबर, 1970 और 14 अप्रैल, 1971 को और आदेश किए थे ;

और यतः, मुझे प्राप्त जानकारी पर विचार करने के पश्चात्, मेरा यह समाधान हो गया है कि उस संघ राज्य-क्षेत्र में स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि उस राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि उस संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम-उल्लिखित आदेश के अधीन

मेरे द्वारा निलम्बित अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन निलम्बित रहना चाहिए और उस आदेश में बनाय गये आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध दो वर्ष के बाद भी प्रवर्तित रहने चाहिए ;

अतः अब, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा निदेश देता हूँ :—

- (क) कि अक्तूबर 1971 के 16 वे दिन से तीन मास की और अवधि के लिए प्रथम-उल्लिखित आदेश के खण्ड (क) के आधार पर अधिनियम के निलम्बित उपबंधों का प्रवर्तन निलम्बित रहेगा और उक्त आदेश के खण्ड (ख) के आधार पर बनाये गये आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध प्रवर्तित रहेंगे ; और
- (ख) कि तत्पश्चात् यथासंशोधित प्रथम-उल्लिखित आदेश के खण्ड (क) में आए 'दो वर्ष' शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष और तीन मास" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

नई दिल्ली-4,

अक्तूबर 12, 1971 ।

व० ब० गिरि,

राष्ट्रपति ।

[सं० एक० 10/26/71-एस० आर०]

के० आर० प्रभू, संयुक्त सचिव ।

